मयंक शेखर 13.9.2001 (दैनिक ट्रिब्यून)

नेपाल-चीन की बढ़ती नजदीकियत

नेपाल नरेश वीरेन्द्र का चीन की पांच-दिवसीय यात्रा पर जाना ऐसे समय में मायने रखता है जब नेपाल में सक्रिय चीन समर्थित माओवादी कम्युनिस्ट गुट (एमसीसी) और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गठजोड़ को भारत विरोधी गतिविधियां हवा देकर उफान पर है।

इस यात्रा की तैयारी के सिलसिले में 21 फरवरी को चीन के रक्षामंत्री जनरल ची हाओतयन काठमांडू पहुंचे और दो दिनों तक उनकी नेपाल के रक्षामंत्री महेश आचार्य से कई दौर की बातचीत होती रही। बातचीत का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया।

भारत में जो समाचार पहुंचा उससे तो यह जाहिर होता है कि बातचीत में सिर्फ नरेश वीरेन्द्र के दौरे से सम्बन्धित मुद्दे थे और 26 फरवरी को वाकई वीरेन्द्र चीन पहुंच भी गए। लेकिन इस बात की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हथियारों की खरीद के बारे में भी कुछ बातें हुई हैं। 1988 में भी नेपाल ने चीन से बड़े पैमाने पर चोरी छिपे हथियार खरीदे, जिनका पता आखिरकार भारत को चल गया और भारत ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। क्योंकि उन हथियारों में विमान भेदी तोपें तथा बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थीं। दिसंबर 1999 में काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आईएसआई द्वारा तैयार की गई योजना के तहत भारतीय विमान के अपहरण के बाद जो भारत-नेपाल सम्बन्ध में खटास पैदा हुई उसे मधुर करने के प्रयास में पिछले वर्ष जून में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला भारत आए।

हालांकि सफलता उन्हें आंशिक रूप से ही मिली, लेकिन ऐसा लगा मानो महौल बदल रहा है, लेकिन तब तक 2001 शुरू होते-होते रितिक रोशनवाली घटना हो गयी जिससे जितनी देर से गाड़ी पटरी पर आयी थी उतनी जल्दी में उतर गयी। रितिक रोशन वाले मामले को उछालने की साज़िश भी भारत विरोधी गतिविधियों का एक हिस्सा था, क्योंकि जिस टीवी यूनिट ने पहली बार यह मामला उछाला उसका संचालक एक पाकिस्तानी निकला और वो उस घटना के बाद ही लापता हो गया।

भारत का नेपाल से सहज रूप में रिश्ता बनता है। इसलिए उस स्थिति में भारत की चिंता स्वाभाविक है जब नेपाल ऐसे देशों को अपना हितैशी माने जो भारत के प्रतिद्वंद्वी हैं।

खासकर चीन से नजदीकियत तो और भी मायने रखती है, क्योंकि भारत को हमेशा इससे खतरा बना रहता है। पाकिस्तान तो बहरहाल इन दिनों लगातार इस कोशिश में जुटा है कि भारत के अंदर कभी नेपाल तो कभी बंग्लादेश के जरिए किसी न किसी रूप में उपद्रव मचाया जाए। इस काम में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद मिली चीन से जो भारत की आजादी के समय से ही पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए इस काम में जुटा है। इधर पाक परमाणु कार्यक्रम में चीन का सहयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है।

भारत से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार तो हासिल कर लिए, लेकिन तब भी वो अच्छी तरह जानता है कि भारत से टकराव की हालत में उसकी हार निश्चित है। जबकि ठीक उसके विपरीत चीन से टक्कर मोल लेना भारत को महंगा पड़ सकता है। इन दो परिस्थितियों ने चीन और पाकिस्तान के बीच इस एक बिन्दु पर सहमति ला दी कि क्यों न पड़ोसी देशों को भारत का भय दिखाकर उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा की जाए, जिसका उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, सबके सब आ गए चक्कर में जिसका सबूत है कि आज ये सारे देश भारत विरोधी केन्द्र बने हुए हैं। हालांकि इस बीच म्यांमार और बांग्लादेश से सम्बन्ध बेहतर बनाने के लिए भारत की ओर से पुरजोर कोशिश हुई है, और वो सफल चल रही है। लेकिन नेपाल में सरकारी और गैरसरकारी स्तर से चल रहें कई मामले भारत के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं जो भारत को नेपाल से अपने सम्बन्ध के विषय में नई सोच अपनाने के लिए एक प्रकार से बाध्य कर रहे हैं।

अब यह नेपाली नीति निर्धारकों को तय करना है कि वो चीन को अपना ज्यादा मददगार मानते है या भारत को जिसकी नेपाल में रिश्तेदारी के साथ-साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी है।

नेपाल का चीन की ओर मुखातिब होना निश्चित रूप से उसकी असुरक्षा की भावना से जुड़ी है। इसलिए आज यह याद दिलाना जरूरी हो गया है कि नरेश वीरेन्द्र के पूर्वज महाराज त्रिभुवन ने अपनी ओर से पहल करके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया था कि वो नेपाल की रक्षा व विदेश नीति संभालने की ज़िम्मेदारी लेलें, लेकिन पं. नेहरू ने अस्वीकार कर दिया था।

महाराज त्रिभुवन ने राणाशाही का तख्तापलट किया था और उनके प्रति भारत की सहानुभूति थी, जबकि राणाओं ने भारत से अच्छे सम्बन्ध बना रखे थे। 1962 में भारत-चीन युद्ध में भारत की हार के बाद नेपाल को लगा कि चीन को ही ज्यादाभरोसेमंद माना जाए। भारत-नेपाल सम्बन्धों का इतिहास बताता है कि वीरेन्द्र के पिता महाराज महेन्द्र के समय में चीन से संपर्क बढ़ाने और भारत से दूरी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ।

1962 की लड़ाई के बाद ही यह खुलकर सामने आ गया, जब नेपाल ने भारत के साथ सैनिक सम्बन्ध तोड़ लिए और वहां नेपाल की सुरक्षा के लिए रह रहे भारतीय सैनिकों को बोरिया बिस्तर समेटने को कह दिया।

भारत से करीबी सम्बन्ध बनाने का श्रेय जाता है नेपाली कांग्रेस को, जिनके राजशाही के खिलाफ चलाए गए आन्दोलन में भारत सहयोगी रहा। 1990 में जब वही जनतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई तो सबसे पहले राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने राजमहल के इशारे पर नेपाली कांग्रेस में फूट डाली। इसके पीछे दो उद्देश्य काम कर रहे थे। एक तो यह कि देश में कोई राजनीतिक दल मजबूत न बनने पाए और ऐसी पार्टी सत्ता में न आ पाए जो भारत से ज्यादा दोस्ती का हिमायती हो।

बाद के वर्षों में राजशाही के खिलाफ खूनी आन्दोलन चलाने वाले माओवादी कम्युनिस्टों ने इस काम में महारत हासिल कर ली जिनका भारत विरोध कई रूपों में सामने आ रहा है। 1976 से माओवादियों की सक्रियता बढ़ी है जब तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पहली बार पाकिस्तान गए और उसके बाद एमसीसी ने आईएसआई से सांठगांठ की।

अभी यह गठजोड़ नेपाल में भारतीय शैल की पढ़ाई वाले स्कूलों पर हमला करता है मधेसिया कहलाने वाले भारतीय मूल के लोग को निशाना बनाए हुए है और अलग गोरखालैंड राज्य की मांग मनवाने के लिए दार्जिलिंग में नए सिरे से हिंसात्मक आन्दोलन चलाने गोरखा मुक्ति आन्दोलन के नेता मुव्वा के सहयोगि को छापामार युद्धकला भी सिखाता है।

प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला 195 के भारत-नेपाल मैत्री संधि के पुनर्नवीकरण बात करके गए ते जिसके तहत नेपाल द्वा किसी और देश से हथियारों की खरीद मनाही है। अब नेपाल अपने यहां संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को प्रशिक्षण देने के नाम पर एक सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना बना रहा है। इस संधि के पुनर्वीकरण के प्रति नेपाल गंभीर नहीं मालूम पड़ता। वास्तव में भारत को उसी समय नेपाल की नीयत का पता चल गया था जब पाक अफगान आतंकवादियों ने नेपाल की जमीन पर भारतीय विमान का अपहरण किया। आज उस समय नेपाल ने चीन से निकटता बढ़ानी शुरू की है, जब नेपाल तिब्बत सीमावर्ती गांवों में चीन की मदद से जगह-जगह एमसीसी ने हथियार प्रशिक्षण केन्द्र खोल रखे है जिनके भारत के उत्तरपूर्व में सक्रिय उल्फा तथा नागा उग्रवादियों से ताल्लुकात है।